

जवाहरलालनेहरूराष्ट्रीयशहरीनवीकरणमिशन

यह लेख में बहुत ही समस्याएं हैं। कृपया इसे बेहतर बनाने में मदद करें या चर्चा पृष्ठ पर इन मुद्दों पर चर्चा करें। (इन टेम्पलेट संदेशों को कैसे और कब हटाएं जानें)

इस लेख को अद्यतन करने की आवश्यकता है। (अगस्त 2012)

सत्यापन के लिए इस लेख हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। (अक्टूबर 2015)

इस लेख में ऐसी सामग्री है जो विज्ञापन की तरह लिखी गई है। (फरवरी 2016)

जवाहरलालनेहरूराष्ट्रीयशहरीनवीकरणमिशन (JNNURM) JnNURM कालोगो। Jpg

जेएनएनयूआरएम योजना जल आपूर्ति। जेपीजी भोपाल नगर निगम के तहत बारात नगर भेल में ओवरहेड वाटर टैंक क्षमता 3 मिलियन लीटर देश भारत 3 दिसंबर 2005

कोलॉन्च किया गया बंदरहता है 2014 स्थिति AMRUT

द्वारा सफल हुई जवाहरलालनेहरूराष्ट्रीयशहरीनवीकरणमिशन (JNNURM)

शहरी विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशाल शहर-

आधुनिकीकरण योजना थी। इसने सात वर्षों में \$ 20

बिलियन से अधिक के कुल निवेश की परिकल्पना की। इसका नाम पं। के नाम पर रखा गया है। जवाहरलालनेहरू,

भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस योजना का आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 3 दिसंबर 2005 को उद्घाटन किया गया था [1]

एक कार्यक्रम के रूप में जिसका उद्देश्य शहरों में जीवन और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना था। 2005 में इसे सात साल की अवधि (मार्च 2012 तक)

के लिए शुरू किया गया था ताकि शहरों को अपने नागरिक सेवा स्तरों में चरणबद्ध सुधार लाने के लिए एक दम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार ने मिशन की अवधिका कार्यकाल दो साल बढ़ा दिया था, यानी अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014

तक। जेएनएनयूआरएम एक बहुत बड़ा मिशन था,

जो मुख्य रूप से भारतीय शहरों पर केंद्रित शहरी समूह के संदर्भ में विकास से संबंधित है। जेएनएनयूआरएम का उद्देश्य शहरों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की रणनीति द्वारा 'आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, न्यायसंगत और उत्तरदायी शहर' बनाना है,

बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर (बीएसयूपी) का प्रावधान [2]

और मजबूत करने के लिए व्यापक शहरी क्षेत्र में सुधार 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार नगरपालिका शासन।

अंतर्वस्तु

1 संरचना

1.1 उप-मिशन

1.2 उद्देश्य

1.3 अवधि

1.4 कार्यान्वयन तंत्र

2 कवरेज

3 कार्यान्वयन

3.1 राज्य स्तर पर सुधार

3.2 शहर के स्तर में सुधार

3.3 परियोजनाओं की स्वीकृति

4 मिड टर्म मूल्यांकन शहर की श्रेणियों के अनुसार

5 फंडिंग शेयर

6 चिह्नित शहरों की सूची

7 यह भी देखें

8 सन्दर्भ

9 बाहरी लिंक संरचना

उप-मिशन

JnNURM मुख्य रूप से अपने कार्यक्रम में दो उप-मिशन शामिल करता है:

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित शहरी अधोसंरचना और शासन के लिए उप-मिशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन और पुराने शहर के क्षेत्रों के पुनर्विकास पर ध्यान देने के साथ।

[उद्धरण वांछित]

शहरी गरीबों (बीएसयूपी) को बुनियादी सेवाओं के लिए उप-मिशन [2] आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा मलिन बस्तियों के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशासित किया गया है। [3]

स्लम सुधार और पुनर्वास के लिए JNNRUM के तहत एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP)

इसके अतिरिक्त, इसके दो और घटक हैं: [4]

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए उप मिशन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित, लघु और मझौले शहरों के एकीकृत विकास (IDSMT) और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जिसका उद्देश्य कस्बों और शहरों में शहरी शहरी ढांचागत सुधार को इसके दायरे में लाना है। [5]

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MHUPA) द्वारा प्रशासित एकीकृत आवास और स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (IHSDP) के लिए उप-मिशन की परिकल्पना की गई और 1993-94 में इसे पूरी आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति सुविधाओं के साथ प्रदान किया गया। । यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया गया है। [6]

उद्देश्य

एकीकृत विकास के संदर्भ में अवसंरचनात्मक सेवाओं से संबंधित ध्यान मिशन के तहत शामिल किया जाना है।

संपत्ति निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन [उद्धरण वांछित] के बीच संबंधों को सुरक्षित करके ढांचागत सेवाओं को साबित करने वाले क्षेत्र के अनुसार शहरों की आत्मनिर्भर क्षमताओं को कुशल और बढ़ाएं।

शहरी अवसंरचना सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिए धन का पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करें।

पेरी-शहरी क्षेत्रों, आउट ग्रोथ, शहरी गलियारों सहित चिन्हित शहरों का योजनाबद्ध विकास, ताकि शहरीकरण विवादित तरीके से हो।

शहरी गरीबों के लिए सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देने के साथ नागरिक सुविधाओं और उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाएं।

शहरी नवीकरण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, यानी, भीड़ को कम करने के लिए आंतरिक (पुराने) शहरों के क्षेत्र का फिर से विकास। [a]

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, जिसमें किफायती कीमतों, बेहतर आवास, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर कार्यकाल की सुरक्षा शामिल है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की अन्य मौजूदा सार्वभौमिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है।

अवधिदिसंबर 2005 सेमिशनकीअवधिसातसालकीहै।इसअवधिकेदौरान, मिशननेभागलेनेवालेशहरोंकेसततविकासकोसुनिश्चितकरनेकीमांगकी।मिशनकेकार्या न्वयनकेअनुभवकामूल्यांकन 2012

मेंग्यारहवींपंचवर्षीययोजनाकेअंतसेपहलेकियाजाएगा।मिशनकीअवधिकोदोऔरवर्षोंतक बढ़ायागयाथा: 31 मार्च 2014 तक। [उद्धरणवांछित]

कार्यान्वयनतंत्रइसफंडकोराज्यस्तरीयएजेंसियोंकेमाध्यमसेप्रसारितकियाजाताहै, जहांकेंद्रऔरराज्यसरकारोंसेअनुदानलियाजाताहैऔरशहरोंकोअनुदानयासॉफ्टलोनकेरूप मेंपारितकियाजाताहै,

बशर्तेकिउन्होंनेविकासरणनीतियोंकोतैयारकियाहोऔरनिवेशइनरणनीतियोंकेभीतरफिट हो।मिशनपारदर्शिताऔरजवाबदेहीपरजोरदेताहै।यहसेवाप्रदाताओंकोआर्थिकरूपसेआत्म निर्भरबनानेकेलिएसार्वजनिक-निजीभागीदारीऔरलागतवसूलीकासमर्थनकरताहै। [3]

केंद्रसरकारद्वाराअनुदानअनुदानकाहिस्सापूर्वोत्तरकेशहरोंमेंसबसेबड़ेशहरोंमें 35% से 90% तकभिन्नहोसकताहै।अधिकांशशहरोंकोआकारकेआधारपरलागतका 50% या 80% कवरमिलताहै। [covering]

रणनीतिऔरपरियोजनाओंकोतैयारकरनेकेलिएशहरीस्थानीयनिकायोंकीसहायताकेलिए क्षमतानिर्माणभीमिशनमेंशामिलहै।वर्तमानमें, जेएनएनयूआरएमद्वारासड़कनेटवर्क, तूफानजलनालियों, बसरेपिडट्रांजिटसिस्टम, जलआपूर्ति, ठोसअपशिष्टप्रबंधन, सीवेजउपचार, नदीऔरझीलमेंसुधार,

झुग्गीसुधारऔरपुनर्वाससेसंबंधितदसपरियोजनाओंकोकवरकियागयाहै।

कवरेज जे एन एन यू आर एम के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल 2001 की जनगणना के अनुसार शहरों / शहरी समूह (यूएस) का चयन करें जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चुने गए मानदंडों / मानदंडों के अनुसार नीचे दिए गए हैं: [7] 2001 की जनगणना 07 के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर / यूएस 2001 की जनगणना 28 के अनुसार बी शहर / यूएस 1 मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम जनसंख्या C चयनित शहर / यूएस (राज्य की राजधानियाँ और अन्य शहर / धार्मिक / ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के यूएस) 28 कार्यान्वयन विजयवाड़ा में जे एन एन यू आर एम सिटी बस लोफ्लोर बसों का इंडीरियर कोच और रतिरुवनंतपुरम के लिए JNNURM से लोफ्लोर बस को यंबटूर शहर के लिए जे एन एन यू आर एम से लोफ्लोर बस हैदराबाद में एक कम्यूटर बस जो JNNURM के एक भाग के रूप में खरीदी जाती है राज्य स्तर पर सुधार 2012 तक गुजरात ने राज्य स्तर के सुधारों के लिए रैली काने तृत्व किया एक मात्र ऐसा राज्य था जिसने मिशन द्वारा आवश्यक सभी 10 सुधारों को प्राप्त किया। पांच राज्यों ने 10 में से 9 सुधार हासिल किए हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। [9] सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामुदायिक भागीदारी कानून शुरू में धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं, केवल पांच राज्यों ने उन्हें 2009 के रूप में सुधार एजेंडे के हिस्से के रूप में लागू करने के लिए प्रबंध किया है। [10] हालांकि, 2012 तक 31 राज्यों में से 22 द्वारा सामुदायिक भागीदारी कानून बनाए गए हैं, और 27 राज्यों द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून बनाए गए हैं। 20 राज्यों ने राज्य स्तर से ULBs तक पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की जिम्मेदारी विकेंद्रीकृत की थी और 19 नए शहर नियोजन कार्यों के लिए ऐसा किया था। [९]

पश्चिम बंगाल परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा JNNURM योजना की एक बस का उपयोग कोलकाता की राजधानी कोलकाता में किया गया है शहर के स्तर में सुधार 2012 तक, विशाखापत्तनम, सूरत और पुणे को सभी 8

शहरस्तरकेसुधारोंकोपूराकरनेकागौरवप्राप्तथा।चेन्नई, ग्रेटरमुंबईऔरहैदराबादने 8 मेंसे 7 सुधारहासिलकिए। 67 शहरोंमेंसे, 30 नेसंपत्तिकरसंग्रहकेलिए 90%

लक्ष्यप्राप्तकियाथा, 20

नेजलापूर्तिऔरस्वच्छताकेलिएपूर्णसंचालनऔररखरखावलागतवसूलीहासिलकीथी, लेकिनकेवल 8 नेठोसअपशिष्टकेलिएलागतवसूलीहासिलकीथी। [11]

परियोजनाओंकीस्वीकृति 2009 तक, कुलअनुमानितकार्यक्रमराशिकेआधेकेबराबर billion 440 बिलियन (US \$ 6.4 बिलियन) केनिवेशकीआवश्यकतावाली 415

परियोजनाओंकोमंजूरीदीगईथी।राज्योंकेबीच,

महाराष्ट्रकोमिशनकेतहतअधिकतमपरियोजनाओंकोमंजूरीदीगईहै।शहरोंमें,

बैंगलोरमेंअनुमोदितपरियोजनाओंकीसंख्यासबसेअधिकरहीहै। [१०]

मिडटर्ममूल्यांकनकंसल्टिंगफर्मग्रॉन्टथॉर्नटनद्वारा 2009

मेंकिएगएएकमध्यावधिमूल्यांकननेमिशनकेप्रभारीमंत्रालयोंकेलिएएकनिदेशालयस्थापितकरनेकीसिफारिशकी;

सलाहकारोंद्वारातैयारकीगईशहरकीविकासयोजनाओंकीतैयारीमेंशहरप्रशासनकीअधिक

भागीदारी; पर्यावरणऔरसामाजिकप्रभावआकलनकेदौरानव्यापकहितधारकपरामर्श;

एकराष्ट्रीयखरीदमैनुअलकाविकास;

दोचरणोंमेंपरियोजनाओंकेलिएअनुमोदनप्रक्रियाकोअलगकरना;

बुनियादीढांचेकेलिएधनकेअलावासुधारोंकेकार्यान्वयनकेलिएवितीयसहायताऔरक्षमता

विकास; राज्य-स्तरपरसार्वजनिक-

निजीभागीदारीऔरपूलिंगफंडिंगतंत्रकेलिएनीतियोंकाउपयोग

जैसेकिशहरीविकासनिधिजोतमिलनाडुऔरउड़ीसामेंमौजूदहैं। [१२]